

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 38/2016

जी.सी.एम.एस. संख्या:- 2016/00106

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मुंशी पुत्र हरचन्द
2. पुष्पा बेवा हरी
3. नरेश पुत्र हरी
4. भूरा पुत्र हरी
5. सुनीता पुत्री हरी
6. हंसा बेवा छोटे
7. देवीचरण पुत्र छोटे

सभी जाति कहार निवासीयान मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली  
.....अपीलाटगण/प्रतिवादीगण।

1. सुरेश
2. दिनेश
3. बबली
4. रेशम बेवा मदन

बनाम

पिसरान मदन

जाति कहार निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राज०  
5. तहसीलदार तहसील मासलपुर।

.....रेस्पोंडेन्टगण/वादीगण।

उपस्थित:-

1. श्री रामजीलाल अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांत।
2. श्री गोविन्द चतुर्वेदी अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट।
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक: 10.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली जिला करौली में  
दायर राजस्व वाद संख्या 516/2008 बउनवान सुरेश वगैरह बनाम मुन्शी वगैरह में

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 319, लगायत 322, 324 लगायत 335, कुल किता 16 कुल रकबा 03 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम उचेका पुरा में स्थित है। जिसमें साबिक खसरा नंबर 184, 185 है। उक्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी व कब्जे काश्त की रही हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उक्त आराजीयात को शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता हरचन्द ने सेटलमेन्ट विभाग से सांठ-गांठ करके उक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया। प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त आराजीयात को कब्जे काश्त करने से मना करते हैं तथा उक्त आराजीयात को स्वयं की आराजीयात बतलाते हैं। अतः अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर उक्त आराजीयात का तकास्मा उभयपक्षों में किया जावे, तथा राजस्व रिकार्ड में उसी प्रकार अंकन किया जावे। अदालत मातहत में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसके अनुसार वादीगण का उक्त आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है यह प्रतिवादीगण के पिता हरचंद की खातेदारी की आराजीयात थी, जिस पर प्रतिवादीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे हैं। मातहत अदालत ने उक्त वाद पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 20.04.2016 को इस प्रकार से आदेश पारित किया कि " विवादित आराजीयात खसरा नंबर 319 लगायत 322, 324 लगायत 335 कुल किता 16 कुल रकबा 03 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम उचेका पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली में वादीगण को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण 01 ता 04 को हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। " उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री हरि पुत्र हरचन्द प्रतिवादी का स्वर्गवास दिनांक 17.03.2015 को हो जाने के पश्चात् भी कायम मुकाम की कार्यवाही किए बगैर तथा हरि के वारिसान अपीलांट 03 ता 05 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। मातहत अदालत में वादीगण ने अपने अधिकारों बाबत जमाबंदी पेश किये बगैर दावा वादी कयासी आधार पर डिक्री किये जाने में कानूनी भूल की है। उक्त दावे से संबंधित राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2007 की अक्षर पालना किये बगैर ही मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में कानूनी भूल की है। मातहत अदालत ने विवादित जमीन पर पुश्तैनी तौर पर काबिज होने एवं रेस्पोजेन्ट का गत 40 साल से विवादित जमीन पर कब्जा ना होते हुये भी

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि शिमला पुत्री मदन निवासी राजौर को रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 ने बिना पक्षकार बनाये दावा पेश कर अहम् कानूनी भूल की है, जबकि रेस्पोंडेंटगण द्वारा शिमला पुत्री मदन को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था क्योंकि विवादित आराजीयात में उसके भी हित प्रभावित होते हैं। आगे कथन किया कि मातहत अदालत ने निर्णय व डिक्री हरि पुत्र हरचन्द प्रतिवादी का स्वर्गवास दिनांक 17.03.2015 को हो जाने के पश्चात् भी कायम मुकाम की कार्यवाही किए बगैर तथा हरि के वारिसान अपीलांत 03 ता 05 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2016 को अपास्त किया जावे।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात उभयपक्षकारान की पैतृक संपत्ति है जिस पर दोनों पक्षों का समान अधिकार है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में भी उभयपक्षकारान को समान हिस्से का खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। जो विधिक व कानूनन रूप से सही है। अपील अपीलांत मात्र रेस्पोंडेंटगण को बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से पेश की गई है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2016 को पश्चात् दिनांक 01.07.2016 की अंतिम डिक्री जारी की जा चुकी है। अपीलांत द्वारा केवल प्राथमिक डिक्री की ही अपील की पेश की गई है। अंकित डिक्री की अपील ही नहीं की गई है। प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरुद्ध पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। प्राथमिक व अंतिम डिक्री के दो निर्णयों के विरुद्ध एक अपील संधारण योग्य नहीं होती है। 2014 आर0बी0जे0 पेज 342 पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने प्रकरण अनुवानी जीतसिंह बनाम गुरुदेव कौर में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि "प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरुद्ध अलग-अलग अपीलें पेश करनी चाहिए, एक अपील में टेनेबिल नहीं है। अपीलार्थी को प्राथमिक व अंतिम

मुंबई न्यायालय  
अपील संख्या 38/2016

डिक्री के विरुद्ध अलग-अलग अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थीं। इसी प्रकार से 2013 आरबी0जे0 पेज 371 पर प्रकरण अनुवानी हासन व अन्य बनाम श्रीमती जुबेदा व अन्य में माननीय मज्दल की एकलपीठ ने दो आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई एक अपील को संधारण योग्य नहीं माना है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.04.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2016 के विरुद्ध केवल एक ही अपील पेश होने के कारण अपील संधारण योग्य नहीं होने के कारण अपील अपीलांत स्वारिज की जाती है।

10. पत्रावली फंसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 10.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम शिन्हा) 23  
संजय अपील प्रविधायी,  
सवाई मांगोपुर